दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सि.मू. (वाणि. बौ.सं.अनु.-व्या.चि.) 86/2022

बेनेट कोलमैन और कंपनी लिमिटेड .... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री हेमंत सिंह, सुश्री ममता रानी झा, सुश्री आकांक्षा सिंह, सुश्री सौम्या खंडेलवाल और सुश्री प्रज्ञा जैन, अधिवक्तागण

बनाम

ई मनोरंजन टीवी एलएलसी और अन्य ... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री प्रिया अदलखा और सुश्री देवयानी नाथ, प्रत्यर्थी-1 के अधिवक्तागण
श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, कें.स.व.अ. सह श्री श्रीश कुमार मिश्रा, श्री अलेक्जेंडर मथाई पाइकाडे और श्री कृष्णन वी., प्रत्यर्थी-2 के अधिवक्तागण ।

सि.मू. (वाणि. बौ.सं.अनु.- व्या.चि.) 243/2022

बेनेट, कोलमैन और कंपनी लिमिटेड ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री हेमंत सिंह, सुश्री ममता रानी झा, सुश्री आकांक्षा सिंह, सुश्री सौम्या खंडेलवाल और सुश्री प्रज्ञा जैन, अधिवक्तागण

बनाम

ई1 मनोरंजन टीवी, एलएलसी अन्य .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री प्रिया अदलखा और सुश्री देवयानी नाथ, प्रत्यर्थी-1 के **अधिवक्तागण**
श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, कें.स.व.अ. सह श्री श्रीश कुमार मिश्रा, श्री अलेक्जेंडर मथाई पाइकाडे और श्री कृष्णन वी., प्रत्यर्थी-2 के अधिवक्तागण ।

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. हरि शंकर

निर्णय (मौखिक)
16.11.2023

सि.मू. (वाणि. बौ.सं.अनु.- व्या.चि.) 86/2022 में अंत.आ. 19852/2023 (सि.प्र.सं. का आदेश 11 नियम 1 (10))

सि.मू. (वाणि. बौ.सं.अनु.- व्या.चि.) 243/2022 में अंत.आ. 19851/2023 (सि.प्र.सं. का आदेश 11 नियम 1 (10))

1. यह याचिकाकर्ता बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा व्यापारचिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 57[1] के अधीन दायर याचिकाओं में प्रत्यर्थी 1 द्वारा दायर आवेदन हैं। याचिकाकर्ता अपनी याचिकाओं में व्यापार चिह्न पंजीकरण में सुधार करने के लिए उसमें से [redacted] चिन्ह को हटाने की मांग करता है, जो प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में वर्ग 38 में पंजीकरण संख्या 2340887 और वर्ग 38 और 41 में 1252812 के तहत पंजीकृत है।

2. प्रत्यर्थी 1 ई! एंटरटेनमेंट टेलीविज़न, एलएलसी ने याचिकाकर्ता की सुधार याचिकाओं के जवाब में दायर अपने प्रतिकथन में अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील दी है कि वह अपने ट्रेडिंग स्टाइल के रूप में इस चिह्न का उपयोग 1990 के दशक की शुरुआत से कर रहा है। इसकी प्रस्तुति के समर्थन में, प्रत्यर्थी 1 ने "ई एंटरटेनमेंट टीवी

3. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी 1 के प्रतिकथन के परिणामस्वरूप अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया है। दोनों पक्षों ने दस्तावेजों के साथ-साथ अपने-अपने गवाहों की सूची भी दाखिल की है।

4. इस स्तर पर, प्रत्यर्थी 1 ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सि.प्र.सं.) के आदेश 11 नियम 1 (10)[2] के अधीन इन आवेदनों को प्रस्तुत किया है। ये आवेदन अनिवार्य रूप से यूट्यूब वीडियो क्लिप को अभिलेख पर रखना चाहते हैं, जो आवेदन के अनुसार, यूआरएल लिंक https://www.यूट्यूब.com/watch?v=uMl3pSL2GA, जिसका उल्लेख लिखित बयान में किया गया है, से मेल खाता है। लिखित कथन में संदर्भित है। इस स्तर पर उक्त क्लिप को अभिलेख पर रखने की मांग का औचित्य इनमें से प्रत्येक आवेदन के पैरा 3 से 5 में पाया गया है, जिसे पुन: इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है:

> "3. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने प्रति-कथन में कहा है कि वह नाम/चिह्न E के अधीन 1990 के दशक की शुरुआत से अपने ट्रेडिंग स्टाइल के रूप में बड़े पैमाने पर, लगातार और निर्बाध रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इसके उपयोग और ब्रांड प्रतिष्ठा के समर्थन में विभिन्न दस्तावेजों को आधार बनाया है और दायर किया

है, जिसमें https://www.यूट्यूब.com/watchv=uMI3pSL2A लिंक पर उपलब्ध 'ई एंटरटेनमेंट टीवी 1993 ईयर इन रिव्यू' शीर्षक वाला यूट्यूब वीडियो भी शामिल है। यह सच है कि जब किसी यूट्यूब वीडियो के अंशों को दस्तावेज़ के रूप में सहेजा जाता है, तो मीडिया सामग्री परिणामी फ़ाइल में प्रदर्शित नहीं होती है। इसलिए, 26 दिसंबर, 2022 के दस्तावेजों की सूची में पेज 15-17 पर यूआरएल और डाउनलोड की तारीख दिखाने वाला प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर स्क्रीनशॉट वास्तव में खाली है।

4. परिणामस्वरुप, वर्तमान समय में उपरोक्त यूट्यूब वीडियो का स्क्रीनग्रैब, जो न्यायालय की फाइल में है, प्रत्यर्थी संख्या 1 का व्यापारचिन्ह E प्रदर्शित नहीं करता है। व्यापारचिन्ह को प्रदर्शित कर रहा स्क्रीनग्रैब, जो उसी वीडियो लिंक से उत्पन्न हुआ है, को इस माननीय न्यायालय के त्वरित संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

5. यह प्रस्तुत किया गया है कि स्क्रीन ग्रैब की प्रामाणिकता के समर्थन में संबंधित वीडियो फ़ाइल के साथ उपरोक्त दस्तावेज़ दाखिल करना प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले को साबित करने और वर्तमान विवाद के उचित निर्णय के लिए आवश्यक है। इसलिए, प्रत्यर्थी सं 1 माननीय न्यायालय से https://www.youtube.com/watchv=uMI3pSL2GA लिंक पर उपलब्ध 1993 के यूट्यूब वीडियो के ताजा स्क्रीनशॉट को अभिलेख पर रखने की अनुमति चाहता है, साथ ही वीडियो फ़ाइल की

डाउनलोड की गई प्रति को एक सीडी. में फाइल करने कि अनुमति चाहता है"।

(जोर दिया गया)

6. इन आवेदनों में प्रार्थना खंड, जो समान है, निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

"तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 इस माननीय न्यायालय से अत्यंत सम्मानपूर्वक निम्न प्रार्थना करता है:

(क) वर्तमान आवेदन को अनुमति दें और 1993 के यूट्यूब वीडियो को नए सिरे से अभिलेख पर रखें;

(ख) प्रत्यर्थी संख्या 1 को 1993 के यूट्यूब वीडियो की डाउनलोड की गई प्रति एक सीडी में दायर करने की अनुमति प्रदान करें:

(ग) ऐसे अन्य आदेश पारित करें जो माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे और प्रत्यर्थी संख्या 1 को न्याय प्रदान करे।''

7. प्रत्यर्थी 1 की विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रिया अदलखा का कहना है कि इन मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए इन आवेदनों में प्रार्थनाओं को स्वीकार करना आवश्यक है। वह कहती हैं कि प्रत्यर्थी 1 के माध्यम से उपयोगकर्ता की चिह्न के संबंध में 1990 के दशक की शुरुआत से दलील उन मुख्य आधारों में से एक है, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी 1 ने वर्तमान सुधार याचिकाओं के विरोध की मांग की है। इसे स्थापित करने के लिए ऐसे उपयोगकर्ता का प्रमाण अभिलेख पर रखना होगा। वह प्रस्तुत करती है कि वास्तव में, वह वर्तमान आवेदनों द्वारा कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ नहीं प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि लिंक, जिसका स्क्रीनशॉट अभिलेख पर रखने की मांग की गई है, उस

यूआरएल से मेल खाता है जो पहले से ही प्रत्यर्थी 1 द्वारा लिखित बयान के साथ दायर किया गया है और जिसका लिखित बयान विशिष्ट संदर्भ देता है। हालाँकि, तत्समान यूट्यूब वीडियो के बिना यूआरएल किसी काम का नहीं होगा और मामले पर निर्णय लेने में न्यायालय के लिए सहायक नहीं होगा। इसलिए, यह आवश्यक है कि वास्तविक यूट्यूब वीडियो का भी अभिलेख हो। यही कारण है कि, वह प्रस्तुत करती है, कि वर्तमान आवेदन यूट्यूब वीडियो के स्क्रीनशॉट को अभिलेख पर रखने के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो की डाउनलोड की गई प्रति को एक सीडी में दायर करने की अनुमति चाहती हैं।

8. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री हेमंत सिंह आवेदनों का पुरजोर विरोध करते हैं। वह निवेदन करते हैं कि, सबसे पहले, इस तरह का आवेदन ट्रेड मार्क्स अधिनियम की धारा 57 के तहत दायर सुधार याचिका में संधार्य नहीं है। उन्होंने इस संदर्भ में, इस न्यायालय पर लागू बौ.सं.अनु. नियम 2022 के नियम 7 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। उनका कहना है कि नियम 7(ii)[3] में विशेष रूप से पक्षों को अपनी-अपनी दलीलों के साथ सभी दस्तावेज़ दाखिल करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, श्री हेमंत सिंह बताते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 2018 ("मूल पक्ष नियम") के अध्याय VII में नियम 2(i)[4] है। बौ.सं.अनु. नियमों में सि.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 1 (10) के अनुरूप ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके द्वारा प्रतिवादी लिखित विवरण दायर करने के बाद अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करे। वह आगे प्रस्तुत करता है कि बौ.सं.अनु. नियमों का नियम 7 (xiii)[5] प्रत्यर्थी 1 के लिए सहायक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह सि.प्र.सं. या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के ऐसे

किसी भी प्रावधान को बौ.सं.अनु. नियमों में शामिल करने की परिकल्पना नहीं करता है, जो बौ.सं.अनु. नियमों के साथ असंगत हैं। इसलिए, जहां बौ.सं.अनु. नियमों में विशेष रूप से दस्तावेजों को अभिवचनों के साथ दाखिल करने की आवश्यकता होती है, वहां बाद के चरण में दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है, श्री हेमंत सिंह का प्रतिविरोध है कि न्यायालय ऐसी अनुमति देने के लिए सि.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 1 (10) का सहारा नहीं ले सकते हैं। वह **राम सरूप लुगानी बनाम निर्मल लुगानी**[6] मामले में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ के निर्णय को आधार बनाते हैं, ताकि यह प्रस्तुत किया जा सके कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मूल पक्ष नियम और बौ.सं.अनु. नियम सि.प्र.सं. के प्रावधानों पर अभिभावी होंगे, जहां इनके बीच असंगतता है।

9. बिना किसी पूर्वाग्रह श्री हेमन्त सिंह आगे कहते हैं कि, गुणावगुण के आधार पर भी, इन आवेदनों की प्रार्थना को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वह बताते हैं कि सि.प्र.सं. का आदेश XI नियम 1(10) अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने की अनुमति तभी देता है, यदि वे मूल रूप से प्रतिवादी की शक्ति और कब्जे में नहीं थे और, और अगर यदि वे थे, तो प्रत्यर्थी द्वारा लिखित बयान के साथ उक्त दस्तावेजों को दाखिल न करने का पर्याप्त कारण दिखाया जाना आवश्यक है। वह बताते हैं, वर्तमान मामले में वह यूट्यूब वीडियो जिसे प्रत्यर्थी 1 इन आवेदनों के माध्यम से अभिलेख पर रखना चाहता है, यदि आवेदनों में दिए गए कथनों पर विश्वास किया जाए, तो वह निश्चित रूप से प्रत्यर्थी 1 के नियंत्रण में था, प्रत्यर्थी 1 के अनुसार वीडियो उस

यूआरएल के समरूप है जिसे लिखित बयान के साथ दायर किया गया है। यदि ऐसा है, तो श्री हेमन्त सिंह का कहना है कि, किसी तर्कपूर्ण कारण के अभाव में उक्त वीडियो लिंक को लिखित बयान के साथ क्यों दर्ज नहीं किया गया, न्यायालय को इस स्तर पर इसे अभिलेख पर रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जबकि याचिकाकर्ता पहले ही अपनी प्रति दाखिल कर चुका है और दोनों पक्षों ने अपने साक्ष्य भी अभिलेख पर रख दिए हैं। उनका कहना है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इस स्तर पर वह प्रत्यर्थी 1 की प्रस्तुति की सत्यता का परीक्षण कर सकें कि ये एप्लिकेशन जिस वीडियो क्लिप को अभिलेख पर रखना चाहते हैं, वह लिखित बयान में उल्लिखित यूआरएल लिंक https://www.youtube.com/watchv=uMI3pSL2A के समरूप है।

10. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और लागू नियमों के आलोक में मामले की जांच की है।

11. सबसे पहले, मैं श्री हेमंत सिंह की प्रारंभिक आपत्ति को संबोधित करता हूं कि वर्तमान आवेदन बिल्कुल भी संधार्य नहीं हैं, क्योंकि यह कार्यवाही अपने आप में वाद नहीं है, बल्कि व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 57 के तहत एक सुधार याचिका है। ***राम समुकदमा लुगानी*** मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा निर्धारित कानून का पालन करते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस न्यायालय के बौद्धिक संपदा प्रभाग (बौ.सं.अनु.) के सभी मामलों के संबंध में जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना है, उसे बौ.सं.अनु. नियमों द्वारा प्रमुख मुक़दमे द्वारा नियंत्रित किया जाना

चाहिए। सि.प्र.सं. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम और मूल पक्ष नियमों के प्रावधान केवल बौ.सं.अनु. नियमों द्वारा प्रदान की गई सीमा तक ही लागू होंगे।

12. सुधार याचिकाओं से निपटने की प्रक्रिया, जैसा कि श्री हेमंत सिंह ने सही बताया है, बौ.सं.अनु. नियमों के नियम 7 में निहित है। हालांकि, नियम 7 (xiii) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के प्रावधान उस सीमा तक ही लागू करता है जबतक कि वह बौ.सं.अनु. नियमों के साथ असंगत न हों, जो कि ऐसी मूल याचिकाओं पर लागू होते हैं।

13. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा प्रभावी सि.प्र.सं. में संशोधन, उसकी अनुसूची का गठन करते हैं और इसलिए, वह स्वयं वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम का एक अभिन्न अंग हैं। इसलिए, बौ.सं.अनु. नियमों के नियम 7(xiii) में "वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम" के संदर्भ में, इसके दायरे में, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा किए गए सि.प्र.सं. में संशोधन शामिल होंगे, जिसमें आदेश XI नियम 1(10) शामिल है। यहाँ तक कि वह बौ.सं.अनु. नियमों के साथ असंगत नहीं हैं, इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा सि.प्र.सं. में किये गये संशोधन व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 57 के तहत दायर सुधार याचिकाओं पर भी लागू होंगे।

14. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश XI नियम 1(10), उक्त नियम में परिकल्पित पूर्व-आवश्यकताओं पूरा होने पर, लिखित बयान के

साथ दायर दस्तावेजों के अलावा प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने की अनुमति देता है।

15. इसलिए, जिस प्रश्न का समाधान किया जाना है वह यह है कि क्या सि.प्र.सं. का आदेश XI नियम 1(10) व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 57 के अधीन दायर सुधार याचिकाओं के मामले में लागू होगा।

16. श्री हेमंत सिंह के अनुसार निश्चित रूप से नहीं। संदर्भानुसार, बौ.सं.अनु. नियमों के नियम 7(xiii) न्यायालय अधिनियम के केवल वह प्रावधान ही शामिल करेंगे जो बौ.सं.अनु. नियमों के साथ असंगत नहीं हैं। चूँकि बौ.सं.अनु. नियमों के नियम 7(ii) में दलीलों के साथ दस्तावेज़ दायर करने की आवश्यकता होती है, और बाद में दस्तावेज़ दायर करने की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं है, सि.प्र.सं. का आदेश XI नियम 1(10) चाहे इस प्रकार बाद में दायर करने की अनुमति देता है परंतु यह बौ.सं.अनु. नियमों के साथ असंगति में है और इसलिए, लागू नहीं हो सकता।

<u>क्या व्यापारचिन्ह अधिनियम की धारा 57 के तहत सुधार याचिकाओं के मामले में सि.प्र.सं. के आदेश XI नियम 1(10) को लागू किया जा सकता है?</u>

17. मैं श्री हेमंत सिंह की इस दलील से सहमत होने में अपनी असमर्थता स्वीकार करता हूं कि लिखित बयान दायर होने के बाद प्रतिवादी को अभिलेख पर अतिरिक्त दस्तावेज रखने की अनुमति देना बौ.सं.अनु. नियमों के विपरीत होगा । बौ.सं.अनु. नियमों का नियम 7(xiii) विशेष रूप से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का

अनुसरण करता है - और, इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में निहित सि.प्र.सं. में संशोधन वास्तव में मूल याचिकाओं पर लागू होते हैं, यानी व्यापारचिन्ह अधिनियम की धारा 57 के तहत सुधार याचिकाएं। मेरी राय में, ऐसे दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने की अनुमति देना बौ.सं.अनु. नियमों के किसी भी प्रावधान के विरुद्ध नहीं है। *बौ.सं.अनु. नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने से रोकता हो, जैसा कि मूल पक्ष नियमों के अध्याय VII के नियम 14[7] में प्रावधान है।*

18. *वास्तव में, बौ.सं.अनु. नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत सिविल मूल याचिका (जिसमें ट्रेड मार्क्स अधिनियम की धारा 57 के तहत याचिकाएं शामिल हैं) के दस्तावेजों को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित किये गये सि.प्र.सं. आदेश XI नियम 1(7)[8] के अनुरूप संबंधित दलीलों के साथ दाखिल करने की आवश्यकता हो।* ध्यान से पढ़ने पर, यह देखा जाएगा कि नियम 7(ii) में केवल "पक्षों के अन्य सभी सुसंगत दस्तावेज़ भी दाखिल करने की आवश्यकता होगी..." यह निर्दिष्ट किए बिना कि दस्तावेज़ों को समरूप दलीलों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। वास्तव में, बौ.सं.अनु. नियमों के नियम 7(ix)[9] न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाने की स्थिति में सिविल मूल याचिका का उत्तर दाखिल करने की परिकल्पना बिना उस चरण के संबंध में किसी शर्त के करता है जिस पर उत्तर के समर्थन में प्रत्यर्थी द्वारा दस्तावेज दाखिल किए जा सकते हैं। हालांकि, यह कहने की जरूरत नहीं है कि प्रत्यर्थी को सुधार याचिका के जवाब के समर्थन में दस्तावेज दाखिल करने के अधिकार से

वंचित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, जिस चरण में दस्तावेज़ दाखिल किए जा सकते हैं, उसे बौ.सं.अनु. नियमों के नियम 7 में व्याख्या के लिए छोड़ दिया गया है। प्रतिवादी को सुधार याचिका के उत्तर के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के मामले में सि.प्र.सं. के आदेश XI नियम 1(10) का लाभ देने की अनुमति नहीं दी जाएगी इसलिए, आवश्यक रूप से, बौ.सं.अनु. नियमों के नियम 7 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

19. यह तर्क देते हुए भले ही यह मान लिया जाए कि बौ.सं.अनु. नियमों के नियम 7 में निहितार्थ के अनुसार प्रति-कथन/सुधार याचिका के समर्थन में दस्तावेजों को प्रति-कथन/उत्तर के साथ दाखिल करने की आवश्यकता होती है, ऐसी आवश्यकता केवल वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश I नियम 1(7) के अनुरूप होगी। सि.प्र.सं. का आदेश XI नियम 1(10) लिखित बयान के साथ दस्तावेज़ दाखिल करने के अधिकार के अलावा, दस्तावेज़ दाखिल करने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है। इसलिए, यह आदेश I नियम 1(7) का विरोध नहीं करता है न ही, परिणामस्वरूप, ऐसे अधिकार को सुधार याचिका के प्रति-कथन/उत्तर के साथ दस्तावेज़ दाखिल करने की आवश्यकता के साथ असंगति में नहीं कहा जा सकता है, यह मानते हुए कि ऐसी किसी भी आवश्यकता को बौ.सं.अनु. नियमों के नियम 7 के साथ पढ़ा जा सकता है। बौ.सं.अनु. नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्रत्यर्थी द्वारा उत्तर/प्रति-कथन दायर किए जाने के बाद अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने पर प्रतिबंध लगाता हो।

20. उस दृष्टिकोण से, मेरी राय है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. का आदेश XI नियम 1(10) बौ.सं.अनु. नियमों के नियम 7(xiii) के मद्देनजर, सुधार याचिकाओं पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होगा।

21. हालाँकि मैंने आदेश XI नियम 1(10) के तहत अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करने के प्रत्यर्थी के अधिकार के संबंध में मामले की जांच की है, चूँकि वर्तमान आवेदन इसी से संबंधित है, यह सिद्धांत वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश XI नियम 1(4) या (5) के संदर्भ में अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करने के याचिकाकर्ता के अधिकार पर समान रूप से लागू होगा।

22. इसलिए, मेरे विचार में, वर्तमान आवेदनों की संधार्यता के संबंध में श्री हेमंत सिंह की प्रारंभिक आपत्ति तथ्यहीन है और तदनुसार खारिज कर दी गई है।

<u>गुणावगुण के आधार पर</u>

23. <u>गुणागुण के आधार पर</u>, सुश्री अदलखा ने बताया है कि जो क्लिप अभिलेख पर रखने की मांग की गई है, वह वाही क्लिप है जो यूआरएल लिंक <u>https://www.youtube.com/watch?v=uMI3pSL2GA</u> से मेल खाती है जिसका संदर्भ पहले से ही एक लिखित बयान में शामिल है, और जो दायर किए गए लिखित बयान के साथ दस्तावेजों का हिस्सा है। उनका कहना है कि, दुर्भाग्यवश, केवल उक्त यूआरएल लिंक पर क्लिक करने से वीडियो क्लिप सामने नहीं आएगी। वर्तमान आवेदन केवल उसी वीडियो क्लिप को अभिलेख पर रखने के लिए दायर किया गया

है जो यूआरएल से मेल खाता है जो पहले से ही लिखित बयान के साथ दायर दस्तावेजों में से एक है।

24. प्रत्यर्थी 1 जिस यूट्यूब वीडियो क्लिप को वर्तमान आवेदनों के साथ अभिलेख पर रखना चाहता है, वह लिखित बयान के साथ दायर यूआरएल के अनुरूप है या नहीं, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी इस न्यायालय को वर्तमान आवेदनों पर निर्णय करते समय जांच करने की आवश्यकता है। सुश्री अदलखा का कहना है कि यह अनुरूप है। याचिकाकर्ता के लिए उचित स्तर पर इस प्रस्तुतिकरण की सत्यता का विरोध करने का विकल्प हमेशा खुला रहेगा। यह साबित करने की जिम्मेदारी निस्संदेह प्रत्यर्थी 1 पर होगी कि इस आवेदन के साथ दायर वीडियो क्लिप वास्तव में यूआरएल लिंक https://www.youtube.com/watch v=uMI3pSL2GA से मेल खाती हो। इसलिए, इस संबंध में वादी की कोई भी शंका निराधार है।

25. यह न्यायालय उस वीडियो क्लिप की प्रासंगिकता से भी चिंतित नहीं है जिसे इन आवेदनों के साथ अभिलेख पर रखने की मांग की जा रही है या क्या यह उस मामले की पुष्टि करता है जिसे प्रत्यर्थी 1 ने सुधार याचिकाओं के जवाब के माध्यम से प्रति कथन में स्थापित किया है। वीडियो क्लिप की वैधता, सत्यता और प्रासंगिकता ऐसे सभी मामले हैं, जिन्हें याचिकाकर्ता सुधार याचिकाओं की सुनवाई के दौरान चुनौती दे सकता है और यह न्यायालय उस संबंध में सभी बचावों का विकल्प याचिकाकर्ता के लिए खुला छोड़ देता है ताकि उचित चरण में आग्रह किया जा सके।

26. जहां तक वीडियो क्लिप को अभिलेख पर रखने का सवाल है, मेरी राय है कि न्यायालय को इस मामले को न्यायानुसार देखना होगा। अनगिनत बार, उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है और दोहराया है कि सि.प्र.सं. के प्रावधान और अन्य प्रक्रियात्मक प्रावधान पर्याप्त न्याय के विचारों पर अभिभावी नहीं हो सकते हैं। यह भी स्पष्ट है कि, किसी न्यायालय द्वारा किसी मुकदमे पर प्रभावी निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक सामग्री न्यायालय के समक्ष होनी चाहिए।

27. यदि प्रत्यर्थी 1, वर्तमान आवेदनों के माध्यम से, एक ऐसा दस्तावेज़ पेश करना चाहता था जो लिखित बयान से अलग था और जो एक पूरी तरह से नया दस्तावेज़ बनता है, तो शायद स्थिति अधिक विवादास्पद होती। इन आवेदनों में प्रत्यर्थी 1 द्वारा माना गया है कि यूट्यूब वीडियो लिंक, जिसका स्क्रीनशॉट आवेदनों में प्रदान किया गया है, और जिसे प्रत्यर्थी 1 सीडी/पेन ड्राइव के माध्यम से अभिलेख पर रखना चाहता है, वह वास्तव में वो वीडियो है जो यूआरएल लिंक https://www.youtube.com/watch v=uMI3pSL2GA से मेल खाता है, जिसका संदर्भ लिखित बयान में निहित है और जो लिखित बयान के साथ दायर दस्तावेजों में से एक है। इस आवेदन में प्रार्थनाओं को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, यह तय करने के प्रयोजनों के लिए, उस रुख को सही माना जाना चाहिए। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, श्री हेमन्त सिंह विशेष रूप से विवाद की सत्यता का विरोध नहीं करते हैं; उनका एकमात्र निवेदन यह है कि वह इस स्तर पर इसकी सत्यता स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, प्रतिवादी को अपने दावे की

पुष्टि करनी होगी कि क्लिप वास्तव में यूआरएल https://www.youtube.com/watch?v=uMI3pSL2GA से मेल खाती है और वादी का इसके विपरीत दावा करने का अधिकार सुरक्षित है।

28. यह मानते हुए कि यह आवेदन जिस वीडियो क्लिप को अभिलेख पर रखना चाहते हैं, वह यूआरएल https://www.youtube.com/watchv=uMI pSL2GA के समरूप है, यदि यह न्यायालय प्रत्यर्थी 1 को इसे अभिलेख पर रखने के अधिकार से वंचित कर देता है तो यह न्याय का उपहास होगा, विशेष रूप से क्योंकि यूआरएल लिंक https://www.youtube.com/watch v=uMI3pSL2GA का सन्दर्भ लिखित बयान में मौजूद है और यह लिखित बयान के साथ संलग्न दस्तावेजों में से एक के रूप में दायर किया गया है।

29. उस हद तक, वास्तव में, सुश्री अदलखा अपनी बात में सही हैं कि ये आवेदन जिस वीडियो क्लिप को अभिलेख में रखना चाहते हैं, वह वास्तव में कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ नहीं है, क्योंकि यह उसी यूआरएल लिंक https:// www.youtube.com/watchv=uMIpSL2GA के समरूप है जो पहले से ही लिखित बयान के साथ दाखिल दस्तावेजों में से एक है।

यहां तक कि सुधार याचिका के उत्तर/प्रति-कथन के बाद अभिलेख पर अतिरिक्त दस्तावेज़ रखने के प्रत्यर्थी के अधिकार के मुद्दे को भी खारिज कर दिया गया है, इसलिए, प्रत्यर्थी 1 वीडियो क्लिप को अभिलेख पर रखने का हकदार होगा।

30. तदनुसार, याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी 1 के दावे का विरोध करने की स्वतंत्रता है कि, प्रत्यर्थी 1 इन आवेदनों के माध्यम से जिस वीडियो क्लिप को अभिलेख पर रखना चाहता है वह वास्तव में लिखित बयान के साथ दायर यूआरएल लिंक https://www.youtube.com/watch?v=uMI3pSL2GA के समरूप है और याचिकाकर्ता को उक्त वीडियो लिंक की वैधता और प्रासंगिकता के साथ-साथ उस संबंध में अन्य सभी बचावों का विरोध करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि उक्त वीडियो क्लिप को अभिलेख पर रखने के लिए प्रत्यर्थी 1 के आवेदनों को अनुमति दी जानी चाहिए।

31. तदनुसार, दोनों आवेदनों को अनुमति दी जाती है। प्रत्यर्थी 1 को एक पेन ड्राइव में यूआरएल लिंक https://www.youtube.com/watch?v=uMI3pSL2GA पर मौजूद यूट्यूब वीडियो की डाउनलोड की गई प्रति को अभिलेख पर रखने और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को उसकी एक अग्रिम प्रति प्रदान करने की अनुमति दी जाती है।

32. चूँकि वर्तमान दस्तावेज़ को इस स्तर पर अभिलेख पर लेने की अनुमति दी जा रही है, याचिकाकर्ता दस्तावेज़ को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा और आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, जैसा कि यहां ऊपर उल्लेख किया गया है, यूट्यूब वीडियो लिंक की वैधता और प्रासंगिकता और उस संबंध में अन्य बचावों को चुनौती देने वाला एक अतिरिक्त शपथ-पत्र भी दाखिल करेगा ।

33. इन आवेदनों को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

न्या., सी. हरि शंकर

नवंबर 16,2023

आर बी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*